भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 126

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसंपत्तियों की डिजिटल निगरानी

126. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में सामाजिक क्षेत्र की अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित टिकाऊ परिसंपत्तियों की डिजिटल निगरानी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की सहायता लेने पर विचार कर रही है जो ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित प्रत्येक आवासीय इकाई की डिजिटल तस्वीर जियोटैग करके इसे सरकारी वेबसाइट पर डालेगी; और

(घ) क्या इससे सरकार को 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी?

<u>उत्तर</u>

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। संबंधित स्कीम की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के जरिए सहायक व्यवस्था करके मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन की निगरानी की जाती है।

मनरेगा के अंतर्गत, राज्यों से यह कहा गया है कि वे कार्य के तीन चरणों – कार्य के पहले, कार्य के दौरान और कार्य के पश्चात – के दौरान विशिष्ट सॉफ्टवेयर (नरेगासॉफ्ट) में फोटोग्राफ अपलोड करें।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, सड़कों के निर्माण की जांच तथा गुणवत्ता निगरानी की रिपोर्टें गुणवत्ता मानदंडों की फोटोग्राफिक रिकार्डिंग के लिए तैयार किए गए साफ्टवेयर वाली मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर अपलोड की जा रही हैं।

आईएवाई के अंतर्गत सहायता भुगतान को एमआईएस-आवाससॉफ्ट पर कार्य समापन के विभिन्न स्तरों पर फोटोग्राफों की अपलोडिंग के साथ संबद्ध करते हुए स्कीम की प्रगति की निगरानी की जाती है। निर्माण के शुरूआती चरण से हुई वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाले फोटोग्राफों को अपलोड करने पर ही परवर्ती किस्तों से संबंधित भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय आसूचना केंद्र (एनआईसी) फोटोग्राफों के माध्यम से मकानों के निर्माण की प्रगति की निगरानी करने एवं इन्हें अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहले से ही मदद कर रहा है।

*****